Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to implement development programmes under additional Central assistance for Left Wing Extremism affected districts.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : देश के वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित विभिन्न प्रांतों के करीब 82 जिलों में भारत सरकार के द्वारा विकास की योजना समेकित कार्य योजना (IAP) संचालित की गई थी तदुपरांत इस योजना का नाम (अतिरिक्त केद्रीय सहायता) किया गया। योजना के माध्यम से 30 करोड़ रु. आबंटित होते थे और इसके अंतर्गत बिहार के औरंगाबाद/गया जिला सहित 11 जिले शामिल थे। यद्यपि अधिकारियों की गठित समिति के द्वारा (LWE) क्षेत्रों में विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की जाती थी, परंतु निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर भी कतिपय योग्य अधिकारियों के द्वारा विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की जाती थी।

वर्तमान में यह योजना वर्तमान सरकार के द्वारा बंद करके संबंधित राज्यों को इस कार्य के कार्यान्वयन का अधिकार दिया गया है, परन्तु वर्तमान में यह योजना पूर्व की भांति प्रभावी नहीं होने के कारण केद्र सरकार के प्रभावी कार्यान्वयन के अनुरूप नहीं है, जिसके कारण प्रभावित क्षेत्रों में विकास बाधित है। इस संबंध में मेरे द्वारा सदन के माध्यम से कई बार आग्रह किया गया है, परन्तु जवाब असंतोषजनक प्राप्त होता है।

पूर्व की योजना (IAP) और ACA के माध्यम से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों सांसद/एम.एल.ए. की अनुशंसा पर (LWE) क्षेत्रों में विकास कार्यों की अनुशंसाओं पर स्वीकृति प्रदान की जाये तो संबंधित क्षेत्रों में उग्रवादी घटनाओं में काफी कमी आयेगी और विकास की मुख्य धारा से भटके लोगों को राष्ट्र और समाज के निर्माण कार्यों में अग्रसर किया जा सकता है।

मेरा पुनः आग्रह है कि ACA को पुनः केद्र सरकार के द्वारा चालू कर माननीय सांसद/माननीय विधायक की अनुशंसा के आलोक में (LWE) प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए प्रभावी कदम उठाने की कृपा की जाये।